

यह मन्त्रालय और कान्ति विमान में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्चा) : (क) 1961 के जनगणना आंकड़ों के अनुसार भारत में 10.21 लाख नेपाली भाषी लोग हैं।

(ख) जी हाँ, श्रीमान्।

(ग) ज्ञापन में दी गई मुख्य बातें ये हैं कि नेपाली भाषा को निम्नलिखित आधारों पर संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल किया जाय :-

- (i) नेपाली भाषा भारत के लगभग 50 लाख लोगों द्वारा बोली जाती है।
- (ii) नेपाली भाषा दार्जिलिंग और आस-पास के अन्य क्षेत्रों के एक बड़े भाग के लोगों की मुख्य भाषा है। नेपाली भारत के घनिष्ठ मित्र नेपाल की राज्य भाषा है और यह भूटान तथा सिक्किम के अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है। इन देशों के सामाजिक, राज-नैतिक और सांस्कृतिक सम्बन्ध भारत के साथ बहुत गहरे और बड़े मजबूत हैं।
- (iii) देश की नेपाली भाषी जनसंख्या भारत की सुरक्षा का प्रधान अंश है और वे भारत के राजनीतिक जीवन में एक बड़ी भूमिका अदा करने हैं।
- (iv) नेपाली भाषा लोगों को सामाजिक विकास तथा संस्कृति व भाषा के विकास के लिए सुविधाएं नहीं मिल रही हैं।

ज्ञापन में दिये गये प्रस्ताव अतीत में भी प्राप्त हुए थे। भारत सरकार का यह निश्चित मत है कि राष्ट्र के विस्तृत हित में संविधान की आठवीं सूची का विस्तार नहीं किया जाना चाहिए।

चौथी योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सीमेंट कारखाने की स्थापना

1407. श्री गंगाधर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश में सीमेंट का एक कारखाना खोलने का सरकार का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी लागत क्या होगी तथा उससे कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा ?

औद्योगिक विकास मन्त्रालय में उप-मंत्री (श्री सिद्धेश्वर प्रसाद) : (क) मेठर (मध्य प्रदेश) में एक 2,00,000 वार्षिक क्षमता वाला सीमेंट का संयंत्र सीमेंट कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा चालू किया जा चुका है। 1,86,060 मी० टन वार्षिक ब्लास्ट फरनैस स्लेग सीमेंट बनाने हेतु एकक के पर्याप्त विस्तार का प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया गया है तथा औपचारिक मंजूरी जारी हो रही है।

(ख) मेठर की पर्याप्त विस्तार योजना पर 211 लाख रुपये की लागत का अनुमान है तथा इससे 105 नवों को रोजगार मिलने की आशा है।

साइसेंसों के लिए मध्य प्रदेश से प्राप्त अनिर्णीत आवेदन-पत्र

1408. श्री गंगाधर शर्मा : क्या औद्योगिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन उद्योगों के लिए औद्योगिक साइसेंस दिये जाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार को आवेदन-पत्र भेजे हैं तथा जिन पर केन्द्रीय सरकार ने निर्णय नहीं किया है ;